



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 6, 2009/श्रावण 15, 1931

No. 258]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2009/SRAVANA 15, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महाविदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2009

अंतिम जांच परिणाम

विषय : यूरोपीय संघ, अमरीका, चीन जन गण एवं ब्राजील के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एथीलिन-प्रोपीलिन-नॉन-कंज्यूगेटेड-डाइन-मोनोमर (ई पी डी एम) रबड़ के आयातों से संबंधित मामले में मध्यावधि समीक्षा पाटनरोधी जांच।

सं. 15/2/2009-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन एवं उन पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का संकलन एवं क्षति के निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठ भूमि

1. मै. यूनिमर्स इंडिया लिमिटेड, मुम्बई ने पूर्व में यूरोपीय संघ, अमरीका, चीन जन गण एवं ब्राजील (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एथीलिन-प्रोपीलिन-नॉन-कंज्यूगेटेड-डाइन-मोनोमर (ई पी डी एम) रबड़ (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष पाटनरोधी याचिका दायर की थी।

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 16 जून, 2006 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड 1 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 14/18/2004 डी जी ए डी, दिनांक 15-6-2006 द्वारा यूरोपीय संघ, अमरीका, चीन जन गण एवं ब्राजील के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एथीलिन-प्रोपीलिन-नॉन-कंज्यूगेटेड-डाइन-मोनोमर (ई पी डी एम) रबड़ के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे।

3. केन्द्र सरकार ने 19 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 75/2006-सी.शु. द्वारा संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

4. ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तथा आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने यह अभ्यावेदन दिया है कि उत्पाद के एकमात्र विनिर्माता अर्थात् मैसर्स यूनिमर्स इंडिया लिमिटेड, मुम्बई ने फरवरी-मार्च, 2007 से ई पी डी एम का उत्पादन बंद कर दिया है और

उसके द्वारा उत्पादन पुनः शुरू किए जाने की संभावना नहीं है तथा संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क अभी भी जारी है जिससे टायर तथा गैर-टायर क्षेत्रों के वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित रही है। उपर्युक्त के मद्देनजर उन्होंने ई पी डी एम पर पाटनरोधी शुल्क तुरंत समाप्त करने का अनुरोध किया है।

5. मैसर्स यूनिमर्स इंडिया लिमिटेड, मुंबई ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने ई पी डी एम रबड़ का उत्पादन बंद कर दिया है और आई डी अधिनियम 1947 के उपबंधों के अनुसार दिनांक 26-6-2008 से अपने कारखाने को औपचारिक रूप से स्थायी तौर पर बंद घोषित कर दिया है।

6. सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए पाटनरोधी नियम के तहत प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करना अपेक्षित होता है। ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तथा आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुरोध के आधार पर तथा नियमों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27-3-2009 की अधिसूचना संख्या 15/2/2009-डी जी ए डी के तहत पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जाँच शुरू की गई थी।

#### ख. प्रक्रिया

7. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:-

- (i) समीक्षा जांच की शुरुआत के बाद प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार प्रश्नावली का उत्तर तथा आवश्यक सूचना मांगते हुए घरेलू उद्योग, संबद्ध देशों में समस्त ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों तथा ज्ञात आयातकों को अधिसूचित किया;
- (ii) नियम 6 (2) के अनुसार जांच की शुरुआत के बारे में नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को इस अनुरोध के साथ अधिसूचित किया गया था कि वे निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने-अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें;
- (iii) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना मांगने के लिए प्रश्नावलियां भेजीं। संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है;
- (iv) वर्तमान मध्यावधि समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 जनवरी, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 (12 माह) की है;
- (v) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएण्डएस) से अनुरोध किया गया था कि वह पिछले 3 वर्षों और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराएँ, लेकिन इस संबंध में कोई ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए थे;

- (vi) संबद्ध वस्तु के किसी घरेलू उद्योग या घरेलू उत्पादक ने लागत एवं क्षति की सूचना उपलब्ध नहीं कराई है;
- (vii) निम्नलिखित आयातकों और उनकी एसोसिएशनों ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर दिया है और संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क तुरंत समाप्त करने का अनुरोध किया है:
1. मै0 जयश्री पालिमर्स प्रा0 लि0, पुणे
  2. मै0 फिनिक्स यूले लि0, कोलकाता
  3. मै0 स्मरबड़ मिल्स लि0, गुडगांव
  4. ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
  5. फाउंडेशन आफ रबड़ पालिमर मैनुफैक्चरर्स, नई दिल्ली
  6. ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
- (viii) प्राधिकारी ने रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से भारत में ई पी डी एम के विनिर्माताओं की सूची के साथ-साथ उनके विस्तृत पते, फोन/फैक्स नं०, ई-मेल पते तथा क्षति अवधि के लिए उनकी उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन/आयात के आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था;
- (ix) प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों की मौखिक सुनवाई करने के लिए 23 जून, 2009 को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की। घरेलू उद्योग/निर्यातकों का कोई भी प्रतिनिधि सार्वजनिक सुनवाई में नहीं आया;
- (x) ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को इस अनुरोध के साथ 17/7/2009 को प्रकटन विवरण जारी किया गया था कि वे अपने विचार 24-7-2009 तक प्रस्तुत कर दें।

#### ग. विचाराधीन उत्पाद

8. मूल जांच और वर्तमान समीक्षा आवेदन में भी शामिल विचाराधीन उत्पाद यूरोपीय संघ, अमरीका, चीन जन गण एवं ब्राजील के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "एथीलिन-प्रोपीलिन-नॉन-कंज्यूगेटेड-डाइन-मोनोमर (ई पी डी एम) रबड़" है। वर्तमान जांच एक मध्यावधि समीक्षा है और किसी भी हितबद्ध पार्टी ने समीक्षा के क्षेत्र में संशोधन (संक्षिप्तीकरण सहित) का अनुरोध करते कोई निवेदन नहीं किया है। अतः जांच में मूल जांच में शामिल उत्पाद ही शामिल है। संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 40 की उप-शीर्ष संख्या 4002.70 के अंतर्गत 6-अंकीय स्तर पर वर्गीकृत है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और प्रस्तावित जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

9. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एथिलीन-प्रोपीलिन-नॉन-कंज्यूगेटेड-डाइन-मोनोमर (ई पी डी एम) रबड़ है। ई पी डी एम एक सिंथेटिक रबड़ है और ई पी डी एम के तकनीकी विनिर्देशनों को मोटे तौर पर एथिलीन, प्रोपीलिन तथा डाइन अंतर्वस्तु एवं मूनी विस्कोसिटी द्वारा शासित होते हैं। इथाइलीन, प्रोपीलिन और डाइन अंश की विविधता के साथ कम चिपचिपाहट के लिए ई पी डी एम रबड़ के विभिन्न ग्रेड का उत्पादन किया जा सकता है।

10. ई पी डी एम रबड़ का उपयोग प्राथमिक तौर पर रबड़ प्रोफाइलों, ऑटोमोटिव टायरों तथा ट्यूबों, केबलों, आटोमोबाइल पुर्जों में उपयोग में लाए जाने वाले मोजा और ढांचा संबंधी मदों में किया जाता है। इथाइलीन, प्रोपीलिन और डाइन अंश और कम चिपचिपाहट एवं अन्य गुण जिसके लिए ई पी डी एम की खपत होती है सामान्य विशेषता को नाममात्र संशोधित करेगा। ई पी डी एम रबड़ विभिन्न ग्रेडों में हो सकता है तथा इसकी विभिन्न रूपों में आपूर्ति की जा सकती है। इस जांच के अंतर्गत सभी ग्रेडों तथा सभी रूपों में इथाइलीन, प्रोपीलिन विभाजित डाइन रबड़ (ई पी डी एम) आते हैं। ई पी डी एम को प्रमुख औद्योगिक उपयोग टायर और गैर-टायर के विनिर्माण में होता है।

#### घ. घरेलू उद्योग का आधार और क्षेत्र विस्तार

11. मूल जांच में मैसर्स यूनिमर्स इंडिया लि०, मुंबई ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष याचिका दायर की है। वर्तमान जांच में आयातकों और उनके सहयोगियों ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के एकमात्र विनिर्माता द्वारा उत्पादन को रोके जाने को देखते हुए शुल्कों को तत्काल वापस लेने लिए अनुरोध किया है। प्राधिकारी ने रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग (संबंधित प्रशासनिक विभाग) से भारत में ई पी डी एम विनिर्माताओं की सूची के साथ-साथ जांच अवधि सहित क्षति होने की अवधि के लिए उनके विस्तार से पते और उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन/आयात आंकड़े उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है। रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग ने उत्तर में उनके दिनांक 27-5-2009 के पत्र संख्या 25011/7/2009-पी सी-11 द्वारा निम्नानुसार सूचना दी है:-

(क) ई पी डी एम रबड़ का केवल एम विनिर्माता नामतः मै० यूनिमर्स इंडिया लि० है।

(ख) वर्ष 2006-07 में इकाई ने 7 महीने उत्पादन किया, वर्ष 2007-08 में यूनिट में केवल 3 महीने उत्पादन किया और वर्ष 2008-09 में इकाई ने कोई उत्पादन नहीं किया। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) जिसे एक संदर्भ भेजा गया था, ने भी सिफारिश की है कि घरेलू टायर और गैर-टायर उद्योगों के हितों के संरक्षण के लिए ई पी डी एम पर लगे पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाना चाहिए।

**ड.) पाटन निर्धारण**

12. सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का इस जांच में महत्व नहीं है क्योंकि न ही घरेलू उद्योग ने और न ही अन्य हितबद्ध पक्षों ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की हैं। आयातकों एवं उनके प्रतिनिधियों के इस अनुरोध पर कि एकमात्र उत्पादक ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन बन्द कर दिया है तथा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से देश के उपयोक्ता क्षेत्र के हितों को नुकसान हो रहा है, के आधार पर मध्यावधि समीक्षा आरम्भ की गई है।

**च) क्षति एवं क्षति संबंधी निर्धारण**

13. मध्यावधि समीक्षा, आयातकों एवं उनके प्रतिनिधियों के इस अनुरोध पर कि एकमात्र उत्पादक ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन बन्द कर दिया है तथा पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से देश के उपयोक्ता क्षेत्र के हितों को नुकसान हो रहा है के आधार पर आरम्भ की गई है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उस सूचना का संदर्भ लिया है कि उन्होंने ईपीडीएम रबड़ का उत्पादन रोक दिया है और आईडी अधिनियम 1947 के प्रावधानों के संगत प्रावधानों के अनुसार 26 जून, 2008 से अपनी फैक्टरी के स्थाई रूप से बन्द करने की घोषणा कर दी है, प्राधिकारी ने इस तथ्य का संदर्भ लिया है कि रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग (संबंधित प्रशासनिक विभाग) ने सूचित किया है कि मै0 यूनिमर्स इण्डिया लि0 ही ईपीडीएम रबड़ का एकमात्र विनिर्माता है और 2006-07 में इकाई ने 7 महीने उत्पादन किया, 2007-08 में इकाई ने केवल 3 महीने उत्पादन किया और 2008-09 में इकाई ने उत्पादन नहीं किया। प्राधिकारी ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की सिफारिशों का भी संदर्भ लिया है कि घरेलू टायर एवं गैर टायर उद्योगों के हितों का संरक्षण करने के लिए ईपीडीएम पर लगे पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाना चाहिए।

**छ. क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना**

14. यह जांच एक मध्यावधि समीक्षा जांच है और आयातकों/उपयोगकर्ता उद्योग के घोषण पर कि उत्पाद के उत्पाद अर्थात् मै0 यूनिमर्स इण्डिया लि0, मुम्बई ने फरवरी-मार्च, 2007 से ईपीडीएम के उत्पादन को स्थगित कर दिया है तथा उत्पादन शुरू करना संभाव नहीं है और संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क अभी भी जारी है जो टायर और गैर टायर के वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर रहा है, मै0 यूनिमर्स इण्डिया लि0, मुम्बई ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने ईपीडीएम रबड़ का उत्पादन स्थगित कर दिया है और आईडी अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार 26.06.2008 से अपनी फैक्टरी को स्थाई तौर पर बन्द करने की घोषणा कर दी है। इस प्रकार इस मामले में क्षति जारी रहने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि एकमात्र घरेलू उद्योग पहले ही बन्द हो गया है और उसने उत्पादन स्थगित कर दिया था।

**15. आयातकों/उपयोगकर्ताओं और उनके प्रतिनिधियों के विचार****क). अखिल भारतीय रबड़ उद्योग एसोसिएशन**

मै0 यूनिमर्स इण्डिया लि0 जो कि भारत में ईपीडीएम का एकमात्र उत्पादक है ने ईपीडीएम जो देश के टायर तथा गैर टायर रबड़ के वस्तुओं के लिए एक नाजुक अवशिष्ट है का उत्पादन बन्द कर दिया है और उसके उत्पादन को पुनः शुरू करने की कोई मंशा नहीं है। चूंकि ईपीडीएम का घरेलू उत्पादन नहीं होता है इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति होने और भविष्य में क्षति होने का प्रश्न नहीं उठता है। भारतीय टायर उद्योग गैर टायर क्षेत्र जो इस समय 6% से 8% की मजबूत वृद्धि के साथ 20% की निर्यात औसत बनाए हुए है। वैश्विक मंदी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है और अपनी वृद्धि में कमी से उभरने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ईपीडीएम पर जारी पाटनरोधी शुल्क ने उपभोक्ता हितों को काफी

प्रभावित किया है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रबड़ की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों का प्रतिस्पर्धात्मक को भी व्यापक रूप में प्रभावित किया है।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग ने ईपीडीएम रबड़ के उत्पादन को स्थगित कर दिया है और आईडी अधिनियम 1947 के संगत प्रावधानों के अनुसार अपनी फैक्टरी को स्थाई तौर पर दिनांक 26 जून, 2008 से बन्द करने की घोषणा कर दी है। संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का जारी रहना देश के टायर और गैर टायर रबड़ वस्तुओं के उत्पादों के विनिर्माता के लिए हानिकारक है उपर्युक्त को देखते हुए ईपीडीएम पर लगा पाटनरोधी शुल्क तत्काल वापस किया जाना चाहिए जिसे संबद्ध देशों से होने वाले आयातों पर लगाया गया है।

**ख) आटोमोटिव टायर विनिर्माता एसोसिएशन**

मै0 यूनिमर्स इंडिया लि0 जो कि ईपीडीएम का भारत में एकमात्र उत्पादक है ने ईपीडीएम का उत्पादन बन्द कर दिया है। चूँकि ईपीडीएम का देश में उत्पादन नहीं होता है इसलिए घरेलू उद्योग के किसी क्षति के मौजूद होने को समाप्त करता है। ईपीडीएम पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रहने से उपभोक्ता हितों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर रहा है जो उपभोक्ता हितों को प्रभावित कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रबड़ की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को हानि पहुँचा रहा है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में संबद्ध देशों से ईपीडीएम के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।

**ग) ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया-**

ईपीडीएम, ऑटो घटक विनिर्माण उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण निविष्टि है। भारत में ईपीडीएम के एकमात्र उत्पादक मै0 यूनिमर्स इंडिया लि0 ने ईपीडीएम का उत्पादन बंद कर दिया है। चूँकि ईपीडीएम का देश में उत्पादन नहीं होता है अतः घरेलू उद्योग को क्षति होने का प्रश्न नहीं उठता है। बल्कि ईपीडीएम पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से उसकी लागत प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ रहा है।

**घ) रबड़ एवं पॉलिमर विनिर्माता प्रतिष्ठान**

मै0 यूनिमर्स इंडिया लि0 ईपीडीएम इंडिया का एकमात्र विनिर्माता है और उनका संयंत्र पिछले 18-20 महीनों से बंद पड़ा है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने हेतु कोई आधार नहीं है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने के लिए प्राधिकारी द्वारा तुरंत कदम उठाया जाना चाहिए।

16. प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं :-

- (i) रबड़ एवं पॉलिमर विनिर्माता प्रतिष्ठान ने सूचित किया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है और उसने शुल्क को शीघ्र समाप्त किए जाने का अनुरोध किया है।
- (ii) अखिल भारतीय रबड़ उद्योग एसोसिएशन ने अपने पूर्व दृष्टिकोण को दोहराया है और शुल्क को तत्काल समाप्त किए जाने का अनुरोध किया है।
- (iii) ऑटोमोटिव टायर विनिर्माता एसोसिएशन ने सूचित किया है कि मै0 यूनिमर्स का संयंत्र लगभग दो वर्षों से बंद पड़ा है और उन्होंने शुल्क को तत्काल समाप्त किए जाने का अनुरोध किया है।

(iv) ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि पाटनरोधी शुल्क का रद्द किए जाने के कारण क्षति जारी नहीं रह सकती है क्योंकि संबद्ध वस्तु का कोई घरेलू उत्पादन नहीं है और उन्होंने संबद्ध वस्तु पर शुल्क को तत्काल समाप्त किए जाने का अनुरोध किया है।

#### **प्राधिकारी द्वारा जाँच**

17. प्राधिकारी ने घरेलू मै0 युनिमर्स इंडिया लि0 मुम्बई द्वारा प्रस्तुत इस सूचना का संज्ञान लिया है कि उन्होंने ईपीडीएम का उत्पादन बंद कर दिया है और आईडी अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अनुसार दिनांक 26.06.2008 से अपनी-अपनी फैक्टरी के औपचारिक स्थायी समापन की घोषणा कर दी है।

18. प्राधिकारी ने रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग (संबंधित प्रशासनिक विभाग) द्वारा प्रदत्त इस सूचना का संज्ञान लिया है कि ईपीडीएम रबड़ का केवल एक विनिर्माता है अर्थात्-युनिमर्स इंडिया लि0 और; इकाई में वर्ष 2006-07 में 7 महीने के लिए, वर्ष 2007-08 में केवल 3 महीने के लिए उत्पादन हुआ था और वर्ष 2008-09 में इकाई में उत्पादन नहीं हुआ।

19. प्राधिकारी ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की इन सिफारिशों का संज्ञान लिया है कि घरेलू टायर तथा गैर-टायर उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए ईपीडीएम पर पाटनरोधी शुल्क रद्द कर दिया जाए।

20. प्राधिकारी ने देश में संबद्ध वस्तु के आयातकों/प्रयोक्ताओं के इस विचार का भी संज्ञान लिया है कि संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि देश में एकमात्र उत्पादक द्वारा उत्पादन बंद कर दिया गया है।

21. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि:-

- (i) मूल आवेदन में मै0 युनिमर्स इंडिया लि0, मुम्बई, घरेलू उद्योग या और देश में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक था।
- (ii) जैसाकि रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा पुष्टि की गई है, देश में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है।
- (iii) संबद्ध वस्तु के सभी आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा उनके प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से यह मत प्रस्तुत किया है कि चूँकि एकमात्र घरेलू उत्पादक ने उत्पादन बंद कर दिया है अतः संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
- (iv) घरेलू उद्योग के बंद होने के परिप्रेक्ष्य में यदि संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को आगे जारी रखा गया तो संभवतः घरेलू प्रयोक्ताओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- (v) संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क रद्द किए जाने से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होगी क्योंकि देश में कोई घरेलू उद्योग शेष नहीं है।

#### **ज) अंतिम परिणाम:**

22. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना तथा किए गए अनुरोधों और हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों अथवा अन्यथा उपर्युक्त परिणामों में यथा दर्ज सूचनाओं के माध्यम से प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और देश में उत्पादन की स्थिति के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी

इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क रद्द किए जाने की स्थिति में किसी घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।

**झ. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे**

23. प्राधिकारी इस बात से सहमत हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण जारी रहने से अंतिम उत्पादों की कीतों पर क्रमिक क्षयकारी प्रभाव पड़ने तथा अंतिम उत्पादों के घरेलू विनिर्माताओं की बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को रद्द करने से कोई घरेलू उद्योग प्रभावित नहीं होगा क्योंकि वर्तमान में देश में कोई भी संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है।

24. सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करके भारतीय बाजार में मुक्त एवं पारदर्शी प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः बहाल करना है जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को रद्द करने से कोई घरेलू उद्योग प्रभावित नहीं होगा क्योंकि वर्तमान में देश में कोई भी संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है।

**ज. सिफारिशें**

25. इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद कि पाटनरोधी उपायों को रद्द करने से कोई घरेलू उद्योग प्रभावित नहीं होगा क्योंकि वर्तमान में देश में कोई भी संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है; प्राधिकारी का यह विचार है कि यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन जन.गण. तथा ब्राजील से आयातों के संबंध में शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।

26. इस प्रकार जाँच करने के पश्चात, प्राधिकारी दिनांक 15.06.2006 की अंतिम परिणामों संबंधी अधिसूचना सं. 14/18/2004-डीजीएडी जो दिनांक 16 जून, 2006 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I में प्रकाशित हुई थी और दिनांक 19 जुलाई, 2006 को केन्द्र सरकार की अधिसूचना सं. 75/2006-सीमाशुल्क द्वारा अधिसूचित की गई थी, के तहत प्राधिकारी द्वारा संस्तुत मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की सिफारिश करते हैं।

27. इस सिफारिश के परिणामस्वरूप जारी होने वाली केन्द्र सरकार के किसी आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी



**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2009

**Final Findings**

**Subject : Mid-term review Anti-Dumping investigation in the matter relating to imports of Ethylene-Propylene-Non-Conjugated-Diene-Monomer (EPDM) Rubber originating in or exported from European Union, USA, China PR and Brazil.**

**No. 15/2/2009-DGAD.**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty, or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules);

**A Background of the case**

1. M/s. Unimers India Ltd, Mumbai had earlier filed an anti-dumping petition before the Designated Authority, alleging dumping of Ethylene-Propylene-Non-Conjugated- Diene-Monomer (EPDM) Rubber (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from European Union, USA, China PR and Brazil (hereinafter referred to as the subject countries).
2. The Designated Authority vide Notification Number 14/18/2004-DGAD dated 15.6.2006 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I dated the 16<sup>th</sup> June, 2006 had notified its final findings recommending definitive anti dumping duties on imports of Ethylene-Propylene-Non-Conjugated- Diene-Monomer (EPDM) Rubber originating in or exported from European Union, USA, China PR and Brazil .
3. The definitive anti dumping duty was imposed on the subject goods by the Central Government vide Notification No.75/2006-Customs dated 19<sup>th</sup> July, 2006.
4. The All India Rubber Industries Association and Automotive Tyre Manufacturers Association have represented that the sole manufacturer of the product viz., M/s. Unimers India Ltd, Mumbai has suspended production of

2850 GI/09-3

EPDM since February-March, 2007 and is unlikely to resume production and the anti-dumping duty on the subject goods still continues affecting the competitiveness of the tyre and non-tyre sector goods. In view of the above, they have requested for an immediate withdrawal of anti-dumping duty on EPDM.

5. M/s.Unimers India Ltd., Mumbai has also intimated that they have suspended production of EPDM Rubber and declared formal permanent closure of their factory as per the provisions of The ID Act, 1947 with effect from 26.6.2008.

6. The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the Anti Dumping Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti dumping duty. Based on the request of the All India Rubber Industries Association and Automotive Tyre Manufacturers Association, and in accordance with the Rules the Mid-term Review investigation of the anti-dumping duties was initiated by the Authority vide Notification No.15/2/2009-DGAD dated 27.3.2009.

#### B. Procedure

7. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:

- i) After initiation of the review investigation, the Authority notified the domestic industry, all known exporters/producers in the subject countries and known importers, calling for questionnaire responses and necessary information in accordance with Rule 6(4);
- ii) The Embassy of the subject countries in New Delhi was informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.
- iii) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information to the known exporters from the subject countries. None of the exporters from subject countries have responded to the Designated Authority.
- iv) The period of investigation for the purpose of the present mid-term review is 1<sup>st</sup> Jan 2008 to 31<sup>st</sup> Dec 2008 (12 months).
- v) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigations, however no details in this respect were received.

- vi) No domestic industry or domestic producer of the subject goods have provided their cost and injury information.
- vii) The following importers and their associations have responded to the initiation notification and requested for immediate withdrawal of the anti-dumping duty on the subject goods:
  - 1. M/s Jayashree Polymers Pvt Ltd, Pune,
  - 2. M/s Phoenix Yule Ltd, Kolkatta ,
  - 3. M/s Roop Rubber Mills Ltd , Gurgaon,
  - 4. All India Rubber Industries Association ,
  - 5. Foundation of Rubber Polymer Manufacturers ,New Delhi,
  - 6. Automotive Tyre Manufacturers Association.
- viii) The Authority requested the Department of Chemicals and Petrochemicals and the Department of Industrial Policy and Promotion to provide the list of the manufacturers of EPDM in India along with their detailed address, phone/fax numbers, E-mail address and their production capacity and production / import data for the injury period.
- ix) The Authority held a public hearing on 23<sup>rd</sup> June, 2009 to hear the interested parties orally. No representatives of the domestic industry/ exporters attended the public hearing.
- x) Disclosure Statement was issued to the known interested parties on 17.07.2009 requesting them to submit their views by 24.07.2009.

### C. Product under consideration

8. The product under consideration involved in the original investigation and also in the present review application is "Ethylene-Propylene-Non-Conjugated Diene Monomer Rubber (EPDM)" originating in or exported from European Union, USA, China PR and Brazil. The present investigation is a mid-term review and none of the interested parties have made any submission requesting modification (including curtailment) in the scope of the review. Therefore, the investigation covers the product covered in the original investigation. The subject goods are classified under Chapter 40 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading No.4002.70 at six digit level. However, Customs classification is indicative only and, in no way, binding on the scope of the proposed investigation.

9. The product under consideration in the present investigation is Ethylene-Propylene-Non-Conjugated Diene Monomer Rubber (EPDM). EPDM is a synthetic rubber and technical specifications of EPDM are broadly governed by Ethylene, Propylene and Diene content, and Mooney Viscosity. With the variations in

Ethylene, Propylene and Diene Content and for Mooney Viscosity, different grades of EPDM Rubber can be produced.

10. EPDM Rubber is primarily used in rubber profiles, automotive tyres and tubes, cables, hoses and moulded items used in the automobile parts. The changes in Ethylene, Propylene and Diene content and Mooney Viscosity and other characteristics will merely modify the general property for which EPDM is consumed. EPDM Rubber can be of various grades and can be supplied in various forms. This investigation covers all grades of Ethylene-Propylene-Non-Conjugated Diene Rubber (EPDM), in all grades and all forms. The Most important industrial use of EPDM is for the manufacture of tyre and non-tyre rubber products .

D. Standing and scope of the Domestic Industry

11. In the original investigations, M/s Unimers India, Ltd Mumbai had filed the petition before the Designated Authority for imposition of Anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries. In the present investigation the importers and their associations have requested for immediate withdrawal of the duties in view of suspension of production by the sole manufacturer of the subject goods in India. The authority requested the Department of Chemicals and Petro-chemicals (the concerned administrative department) to provide the list of manufacturers of EPDM in India along with their detailed address and their production capacity and production/import data for the injury period including the POI . In response the Department of Chemicals and Petro-chemicals (the concerned administrative department) vide their letter No.25011/7/2009-PC-II dated 27.05.2009 has intimated as follows:

a) There is only one manufacturer of EPDM Rubber namely Unimers India Ltd.

b) In 2006-07 the unit was in production for 7 months, in 2007-08 the unit was in production for only 3 months and in 2008-09 the unit was not in production.

The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) , to whom a reference was made , has also recommended that the anti- dumping duty on EPDM may be revoked to protect the interests of the domestic tyre and non-tyre industries.

**E. Dumping Determination:**

12. Determination of normal value, export price and dumping margin are not relevant in the present investigations as neither the domestic industry nor any other interested parties have submitted the required information. The mid-term review has been initiated on the basis of the requests of the importers and their representatives that the sole domestic producer has stopped production of the subject goods and the continuation of the anti-dumping duty is detrimental to the interests of the user sector of the country.

**F. Injury and Causal link Determination :**

13. The mid-term review has been initiated on the basis of the requests of the importers and their representatives that the sole domestic producer has stopped production of the subject goods and continuation of the anti-dumping duty is detrimental to the interests of the user sector of the country. The Authority has taken note of the intimation of the domestic industry that they have suspended production of EPDM Rubber and declared formal permanent closure of their factory as per the relevant provisions of the ID Act, 1947 from June 26, 2008. The Authority has also taken note of the fact that Department of Chemicals and Petro-chemicals (the concerned administrative department) has intimated that there is only one manufacturer of EPDM Rubber namely Unimers India Ltd, and ; in 2006-07 the unit was in production for 7 months, in 2007-08 the unit was in production for only 3 months and in 2008-09 the unit was not in production. The Authority has also taken note of the recommendations of the Department of Industrial Policy and Promotion that the anti-dumping duty on EPDM may be revoked to protect the interests of the domestic tyre and non-tyre industries.

**G. Likelihood of continuation or recurrence of injury :**

14. Present investigation is a mid-term review investigation and have been initiated at the behest of importers/ user industry informing that the sole manufacturer of the product viz., M/s. Unimers India Ltd, Mumbai has suspended production of EPDM since February-March, 2007 and is unlikely to resume production and the anti-dumping duty on the subject goods still continues affecting the competitiveness of the tyre and non-tyre sector goods. M/s. Unimers India Ltd., Mumbai has also intimated that they have suspended production of EPDM Rubber and declared formal permanent closure of their factory as per the provisions of The ID Act, 1947 with effect from 26.6.2008.

2850 GI/09-4

Thus, the question of examining continuation of injury does not arise in this case as the sole domestic industry has already closed down and suspended production.

15. Views of the Importers/Users and their representative

a. All India Rubber Industries Association-

M/s Unimers India Ltd, the sole producer of EPDM, in India, has ceased production of EPDM, which is a critical raw material for the tyre and non-tyre rubber goods producers of the country, and has no intention of restarting production. Since EPDM is not indigenously produced, the question of any injury to the domestic industry does not and will not arise in future. The Indian Rubber industry non-tyre sector, which hitherto was maintaining a steady growth of 6 to 8%, with an average export growth of 20%, has been severely affected due to global recession and is struggling hard to fight back to its growth trail. Continuation of anti-dumping duty on EPDM is substantially affecting the consuming interest and also blunting the competitive edge of the domestic producers of rubber goods in the international market.

Considering the fact that the domestic industry has suspended production of EPDM Rubber and declared formal permanent closure of their factory as per the relevant provisions of the ID Act, 1947 from June 26, 2008, continuation of the anti-dumping duty on the subject goods will be detrimental to the interests of the manufacturers of tyre and non-tyre rubber goods producers of the country. In view of the above the anti-dumping duty on EPDM should be withdrawn immediately, as imposed on imports from the subject countries.

b. Automotive Tyre Manufacturers Association -

M/s Unimers India Ltd, the sole producer of EPDM, in India, has ceased production of EPDM. Since EPDM is not indigenously produced, the question of any injury to the domestic industry has ceased to exist. Continuation of anti-dumping duty on EPDM is resulting in additional financial burden on consuming interests and affecting their competitiveness substantially affecting the consuming interest and also blunting the competitive edge of the domestic producers of rubber goods in the international market. In view of the

above the anti-dumping duty on EPDM should be withdrawn immediately, as imposed on imports from the subject countries.

c. **Automotive Component Manufacturers Association of India-**

EPDM is an important input required by the auto component manufacturing industries. M/s Unimers India Ltd, the sole producer of EPDM, in India, has ceased production of EPDM. Since EPDM is not indigenously produced, the question of any injury to the domestic industry has ceased to exist. On the contrary, continuation of anti-dumping duty on EPDM is affecting their cost competitiveness.

d. **Foundation of Rubber & Polymer Manufacturers-**

M/s Unimers India Ltd is the sole manufacturer of EPDM India and their plant is lying closed for last 18- 20 months. There is no basis of continuing the anti-dumping duty on the subject goods from the subject countries. The Authority should take urgent steps for withdrawal of the anti-dumping duty on the subject goods from the subject countries.

16. In response to the disclosure statement the following importer's/representatives have submitted their views:

i) The Foundation of Rubber & Polymer Manufacturers has intimated that there is no justification to continue the anti dumping duty on the subject goods from the subject countries and requested early withdrawal of the duty.

ii) The All India Rubber Industries Association has reiterated their earlier views and requested for immediate withdrawal of the duty.

iii) The Automotive Tyre Manufacturers Association has informed that the plant of M/s Unimers is lying closed for nearly two years and requested immediate withdrawal of the anti dumping duty.

iv) The Automotive Component Manufacturers Association of India has intimated that revocation of the anti dumping duty cannot result in continuation of injury as there is no domestic production and requested for immediate withdrawal of the duty on the subject goods.

**Examination by the Authority**

17. The Authority has taken note of the information submitted by the domestic industry M/s. Unimers India Ltd., Mumbai that they have suspended production of EPDM Rubber and declared formal permanent closure of their factory as per the provisions of The ID Act, 1947 with effect from 26.6.2008.

18. The Authority has taken note of the information provided by the Department of Chemicals and Petro-chemicals (the concerned administrative department) that there is only one manufacturer of EPDM Rubber namely Unimers India Ltd, and ; in 2006-07 the unit was in production for 7 months, in 2007-08 the unit was in production for only 3 months and in 2008-09 the unit was not in production.

19. The Authority has taken note of the recommendations of the Department of Industrial Policy and Promotion that the anti-dumping duty on EPDM may be revoked to protect the interests of the domestic tyre and non-tyre industries.

20. The Authority has also taken note of the views of the importers/users of the subject goods in the country that there is no justification of continuing the anti dumping duty on the subject goods as the sole producer in the country has stopped production .

21. Based on the above facts the Authority concludes that:

i) M/s Unimers India Ltd , Mumbai was the domestic industry in the original application and the sole producer of the subject goods in the country.

ii) As confirmed by the Deptt. of Chemicals and Petrochemicals, there is no other producer of the subject goods in the country .

iii) All the importers/users of the subject goods and their representatives have unanimously opined that since the sole domestic producer has stopped production, the anti dumping duty on the subject goods should be revoked.

iv) In view of the closure of the domestic industry, if the anti dumping duty on the subject goods is allowed to be continued any further, it may affect the domestic users adversely.



v) Revocation of the anti dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries may not cause any injury to any domestic industry, the same being not there any more.

#### H. Final Findings:

22. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submissions of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of production in the country the Authority concludes that should the present anti dumping duties be revoked, no domestic industry is likely to be injured.

#### I. Indian industry's interest and other issues

23. The Authority recognises that the continued imposition of anti dumping duties may have cascading effect on the prices of the end products and adversely affect the market competitiveness of the domestic manufacturers of the end products. On the contrary, revocation of the anti dumping measures would not affect any domestic industry since presently there is none producing the subject goods in the country.

24. The purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Revocation of the anti dumping measures would not affect any domestic industry since presently there is none producing the subject goods in the country.

#### J. Recommendations

25. Having concluded that the revocation of the anti dumping measures would not affect any domestic industry since presently there is none producing the subject goods in the country; the Authority is of the opinion that the measure is required to be revoked in respect of imports from European Union, USA, China PR and Brazil.

26. Having examined thus, the Authority recommends withdrawal of the Anti-Dumping Duty in place as recommended by the Authority vide Final Findings Notification No. 14/18/2004-DGAD dated 15.6.2006, published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I on the 16<sup>th</sup> June, 2006 and notified by the Central Government vide Notification No. 75/2006-Customs dated 19<sup>th</sup> July, 2006.

27. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

R. GOPALAN, Designated Authority